239 क लेख – भारतीय राजनीति चौराहे पर
239 ख प्रश्न– श्री राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, पुरैनी बाजार, बिजनौर, उ.प्र. 246762
239 ग प्रश्न– . श्री सत्यदेव गुप्त सत्य, रुदौली, बाराबंकी, उत्तरप्रदेश

भारतीय राजनीति चौराहे पर

अब तक यह स्पष्ट दिख रहा था कि भारतीय राजनैतिक व्यवस्था लगातार गिरावट की दिशा में जा रही है किन्तु पिछले तीन वर्षों से जबसे आम चुनावों के बाद मनमोहन सिंह दुबारा प्रधान मंत्री बने हैं, तब से राजनीति की गिरावट न केवल रूक गई है बल्कि राजनीति गिरावट से मुड़कर चौराहे तक आ पहुंची है। इसका श्रेय भारत की जनता को जाता है, जिसने दल की परवाह न करते हुए अच्छे लोगों को प्राथमिकता देनी शुरू की।

भारत की राजनीति ठीक दिशा में बढ़ रही थी किन्तु सोनिया गांधी के पुत्र मोह ने फिर से संकट खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह सरीखों की चौकड़ी ने किसी तरह सोनिया जी को यह समझाने में सफलता पा ली कि प्रधान मंत्री पद तो नेहरू परिवार का पारिवारिक पद है। राजीव गांधी की अकाल मृत्यु के कारण भले ही राहुल के बालिग होते तक उस पर मनमोहनसिंह खड़ाउँ प्रधानमंत्री हैं किन्तु है तो वह वह नेहरू परिवार रूपी राहुल का ही। इस परिवार मोह ने भारतीय राजनीति को संकट ग्रस्त परिस्थिति में चौराहे पर ला खड़ा किया है जिसका मार्ग या तो प्रबद्ध राजनेताओं को खोजना होगा अन्यथा अन्ततोगत्वा जनता को।

स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसे लोकतंत्र की कुछ समझ है अन्यथा अब तक तो तानाशाही प्रवृत्ति के ही लोगों से भेंट होती रही है। शास्त्री जी को अपवाद माना जा सकता है तथा अटल जी की मजबूरी हो सकती है कि उन्हे अपना पूरा कार्यकाल संघ परिवार की तानाशाही से बचाव में ही लगाना पड़ा। इस समय हमारे समक्ष सबस बड़ा राजनैतिक खतरा है परिवारवाद जिसका सर्वाधिक खतरनाक पक्ष है राहुल की तैयारी और उसकी मजबूत काट हैं
मनमोहनसिंह। यदि किसी भी रूप में मनमोहनसिंह कमजोर होते हैं या किये जाते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिये सर्वाधिक खतरनाक दिशा होगी। अतः हमारी यह मजबूरी है कि जब तक राहुल गांधी के वंशवाद का खतरा समाप्त नहीं होता तब तक मनमोहन सिंह को ढाल के रूप में मजबूती प्रदान करते रहें। नीतिश कुमार या नरेन्द्र मोदी को अभी और तैयारी तक ही सीमित रहना चाहिये अन्यथा उनकी समयपूर्व दौड़ राहुल का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

यदि हम दलगत राजनीति की समीक्षा करें तो सिर्फ जदयू ही एकमात्र ऐसा दल है जहॉ लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र का भारत में स्वाभाविक परिणाम है अव्यवस्था तथा राजनैतिक अव्यवस्था सर्वाधिक जदयू में ही है। दूसरे कम में भाजपा को माना जा सकता है जिसमें भी अव्यवस्था है ही। साम्यवाद एक व्यवस्थित दल तो है किन्तु उसकी विचारधारा इतनी खतरनाक है कि उसके विषय में तो सोचा भी नहीं जा सकता। अन्य सभी दल तो पारिवारिक गिरोह से आगे कुछ हैं ही नहीं। ये तो मात्र अव्यवस्था का लाभ उठाने के उद्देश्य स अस्थायी उछलकूद करने तक सीमित हैं। यह सब होते हुए भी कांग्रेस को अनदेखा करना संभव नहीं क्योंकि कांग्रेस का चरित्र अन्य दलों से भिन्न है। उसमें वंशवाद की गंभीर बीमारी होते हुए भी अन्य अनेक गुण हैं। सोनिया गांधी में भी स्वाभाविक पुत्र मोह भले ही है किन्तु उनका राजनैतिक स्तर उस तरह का नहीं जैसा अन्य अनेक दलों का है। इसलिये अच्छा यही होगा कि केन्द्र में मनमोहनसिंह जी को इतना मजबूत किया जाये कि सोनिया एक सीमा रेखा से नीचे उतरने की हिम्मत ही न कर सके।

अब हम प्रादेशिक राजनीति की समीक्षा करें। बिहार में नीतिश कुमार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जितनी हिम्मत करके बिहार में विधायक निधि को समाप्त किया उसके लिये उनकी बहुत अधिक प्रशंसा होनी चाहिये। बिहार भारत का अकेला राज्य है जिसने कृषि उपज पर से मंड़ी कर खतम कर दिया। भाजपा जैसी साम्प्रदायिक सोच वाली पार्टी के साथ मिलकर सफलता पूर्वक सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं था। मेरे विचार में बिहार में यदि लालू पासवान सरीखे लोग एक भी सीट पाते हैं तो यह वहॉ की जनता के लिये दुखद ही होगा। बिहार के ठीक विपरीत नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की मुस्लिम साम्प्रदायिकता को जिस तरह सबक सिखाया वह भी कोई साधारण बात नहीं। देश भर के नकली गांधीवादियों ने मोदी के विरूद्ध गुजरात में बहुत व्यायाम किया किन्तु वे जरा भी सफल नहीं हो सके। न्यायपालिका की अति सकियता से भी मोदी अब तक सफलता पूर्वक बचते रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी लगभग ठीक ही है जहॉ के कांग्रेसी और भाजपाई मिलकर आपस में चाहे जितना टकराते रहें किन्तु जोगी जैसे खतरनाक व्यक्ति को पनपने नहीं दे रहे। मेरे विचार में तिकड़म के मामले में सम्पूर्ण भारत में जोगी जी की गणना सर्वोच्च में ही होनी चाहिये। फिर भी उनका असफल होना नागरिक जागरूकता का ही प्रतीक है। अन्य प्रदेशों में अभी कोई साफ तस्वीर नहीं उभर रही। केरल में अच्युतानन्दन योग्य व्यक्ति माने जाते हैं। वे यदि मजबूती से डटे रहें तो अच्छा ही होगा। बंगाल में साम्यवाद से पिण्ड छुड़ाने के लिये ममता एक मजबूरी ही थी अन्यथा ममता किसी भी रूप में माया, मुलायम, जय ललिता से भिन्न नहीं। यदि बंगाल में बुद्धदेव का नरम साम्यवादी के रूप में उभरना संभव या उचित न हो तो कांग्रेस भाजपा का ही विस्तार संभव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। माया, मुलायम के बीच ही ध्रुवीकरण दिखता है। जनता चाहे तो कुछ कांग्रेस भाजपा को मजबूत करके माया, मुलायम की ताकत घटा सकते हैं। मेरा तो सुझाव है कि उत्तरप्रदेश की जनता इन चुनावों में माया, मुलायम को पहले की अपेक्षा कमजोर करेगी। मध्यप्रदेश दिग्विजय सिंह जी का गृह प्रदेश है। दिग्विजय सिंह जी की भूमिका को युवराज राहुल का पूर्ण समर्थन माना जाता है। इसके बाद भी मध्यप्रदेश के कांग्रेसी भाजपाई मिलकर दिग्विजय सिंह जी से जैसा सफल मोर्चा ले रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं। अन्य प्रदेशों में अभी स्पष्ट विकल्प दिखने शुरू नहीं हुए हैं। संभव है कि अगले चुनाव तक कुछ और प्रदेश भी वंशवादी तानाशाही से मुक्त हो पायें।

भारतीय मतदाताओं के समक्ष स्पष्ट विकल्प है। यदि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहनसिंह, नीतिश कुमार, नरेन्द्र मोदी सरीखे लोगों के बीच टकराव हो तो आप देश काल परिस्थिति अनुसार स्वयं निर्णय करें अन्यथा सीधा सीधा मनमोहनसिंह को मजबूत करें। केन्द्र में भाजपा के पास न कोई व्यक्ति है न कोई चिन्तन ही है। भाजपा वर्तमान समय में उथली राजनीति कर रही है। उसने जिस तरह तात्कालिक लाभ के लिये कुशवाहा मामले में जल्दबाजी की अथवा अन्ना आंदोलन मे भी लुका छिपी में संलग्न रही वह उसकी गंभीरता को कम कर रही है। भाजपा को कांग्रेस चिन्तन और संघ चरित्र का अनुशरण करना चाहिये था किन्तु वह इसके ठीक विपरीत संघ चिन्तन और कांग्रेस चरित्र को अपना रही है जो उसके लिये घातक है। मनमोहन सिंह के पास कांग्रेस चिन्तन तथा संघ

चरित्र होने से भाजपा कभी नहीं बढ़ सकती जब तक कांग्रेस ही दो फाड़ होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मार ले। भाजपा को चाहिये कि वह प्रतीक्षा करे। यदि सोनिया कभी पुत्र मोह की कोशिश करे तो भाजपा मनमोहन सिंह की मदद करके भारतीय राजनीति को पुनः वंशवाद की ओर जाने से बचा ले। मुझे विश्वास है कि भाजपा तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मिलकर अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे जो चौराहे पर खड़े भारतीय लोकतंत्र को सही मार्ग पर चलने हेतु सहायक बन सके। भारत की जनता सोनिया जी से भी उम्मीद करती है कि जिस तरह उन्होंने अब तक स्वयं को आरोपों से बचाकर सुरक्षित रखा है उसी तरह इस वंशवाद अथवा पुत्र मोह के आरोप से भी बचने का प्रयास करेंगी। आशा है कि लोकतंत्र चौराहे से ठीक लाइन पर चलने लगेगा।

प्रश्नोत्तर

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, पुरैनी बाजार, बिजनौर, उ.प्र. 246762

प्रश्न— ग्यारह नवंबर को व्यवस्था परिवर्तन यात्रा के अन्तर्गत पुरैनी बाजार में पहली बार आपके विचार सुने। महसूस हुआ कि स्वामी दयानन्द विवेकानन्द के बाद भारत आपके माध्यम से विश्व को सामाजिक विषयों पर मौलिक चिन्तन देने की क्षमता रखता है। मैं मानता हूँ कि प्रतिबद्ध चिन्तन अधिकांश लोगों की मजबूरी होती है किन्तु प्रतिबद्ध चिन्तन से आगे बढ़कर स्वतंत्र चिन्तन की दिशा में बढ़ना भी आवश्यक है जिधर आप स्वयं बढ़े भी हैं और हम सबको बढ़ने हेतु प्रेरित भी कर रहे हैं।

आपमें मार्ग दर्शन की क्षमता है। इसीलिये मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आज समाज इतना नीचे क्यों जा रहा है? मानव स्वयं को पशुओं से श्रेष्ठ कहता है किन्तु कभी कभी पशुओं से भी नीचे क्यों चला जाता है। पर्यावरण को नष्ट करने में तो मानव आगे बढ़ ही रहा है किन्तु सामाजिक परंपराएँ भी तोड़ने में मानव आगे जाता जा रहा है। बम्बई में एक पिता ने करोड़पति बनने की लालच में किसी तांत्रिक की सलाह पर अपनी ही लड़की को गर्भवती कर दिया। आपके विचार में मानव इतना क्यों गिरता जा रहा है।

उत्तर— व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं ;1द्ध सामाजिक ;2द्ध असामाजिक ;3द्ध समाज विरोधी। सामाजिक व्यक्ति वह होता है जो असामाजिक तथा समाज विरोधी कार्य नहीं करता। असामाजिक व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक कार्य भी करता है तथा असामाजिक भी। किन्तु समाज विरोधी कार्य नहीं करता। समाज विरोधी वह होता है जो तीनों प्रकार के कार्य करने को स्वतंत्र है।

तीनों प्रकार के कार्य भी अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कार्य करते हुए शेष समय और शक्ति समाज की सहायता में लगाता है वह सामाजिक व्यक्ति माना जाता है। जो व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार की चिन्ता तो करता है किन्तु अपना शेष समय शक्ति अनावश्यक कार्यों में लगा देता है तथा समाज के मान्य सिद्धान्तों का पालन नहीं करता वह असामाजिक व्यक्ति माना जाता है। जो व्यक्ति अन्य कार्यों के साथ साथ समाज द्वारा प्रतिबंधित कार्य भी करता है उस कार्य को अपराध तथा उस व्यक्ति को अपराधी अथवा समाज विराधी कहते हैं।

अपराध अथवा समाजविरोधी कार्य पांच ही माने जाते हैं ;1द्ध चोरी डकैती लूट ;2द्ध बलात्कार ;3द्ध मिलावट कमतौल ;4द्ध धोखा धड़ी जालसाजी ;5द्ध हिंसा बलप्रयोग आतंक। अपराध के लिये आवश्यक है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो, तथा उसकी इच्छा के विपरीत हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य के साथ उसकी सहमति से संभोग किया है तो वह न तो अपराध है न ही समाज विरोधी कार्य। यदि ऐसी सहमति लोभ लालच से भी ली जाये तब भी वह समाज विरोधी कार्य नहीं। सम्भोग किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार है जिसे कोई अन्य बल पूर्वक तब तक नहीं रोक सकता जब तक दोनों की सहमति है।

सहमति के बाद भी समाज के व्यवस्थित संचालन के लिये समाज स्वीकृत नियम या परंपराएँ होती हैं जिनका उल्लंघन असामाजिक कार्य माना जाता है। पिता पुत्री अथवा ससुर बहू के बीच अवैध संबंध समाज स्वीकृत कार्य नहीं माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे किसी कार्य से बचना चाहिये क्योंकि ऐसा कार्य भले ही अपराध न हो किन्तु समाज व्यवस्था के तो विपरीत ही है। समाज का कर्तव्य है कि वह ऐसे कार्य को अनुशासित करे तथा निरुत्साहित करे।

समाज को देश काल परिस्थिति के आधार पर अपनी प्राथमिकताएँ तय करनी पड़ती हैं। सामान्य काल में सामाजिक लोगों का प्रतिशत चार पांच, समाज विरोधी लोगों का एक के आसपास तथा शेष पंचान्नवे प्रतिशत असामाजिक लोगों का होता है। ऐसे काल में समाज को समाज विरोधी तत्वों से कोई खतरा नहीं होने के कारण असामाजिक लोगों से दूरी बना कर रखनी चाहिये। ऐसे समय में असामाजिक लोगों का हृदय परिवर्तन भी करने का प्रयास करना चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक भय भी बनाया जा सकता है। किन्तु जब सामान्य काल के विपरीत समाज विरोधी तत्वों का प्रतिशत एक दो से बढ़कर चार पांच हो जाये तथा सामाजिक लोगों का प्रतिशत घटकर एक दो हो जाये तब ऐसे समय को आपात्काल कहते हैं। आपात्काल में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तथा सामाजिक लोगों का घटता है। ऐसे आपात्काल में सामाजिक लोगों को अपनी प्राथमिकताएँ बदल देनी चाहिये अर्थात् असामाजिक लोगों के साथ दूरी घटा लेनी चाहिये। ऐसे समय में समाज विरोधी तत्व पूरी कोशिश करते हैं कि सामाजिक लोग असामाजिक लोगों से दूरी न घटने दें तभी तो असामाजिक लोग समाज विरोधी तत्वों के साथ जुड़ कर रहेंग। अब यह सोचना सामाजिक लोगों का काम है कि वे असामाजिक तत्वों को अपने साथ जोड़ कर रखने की बुद्धिमानी करते हैं या उन्हें दुत्कार कर रखने की मूर्खता। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे अनेक धर्मगुरूओं पर भी जो वर्तमान समय को आपात्काल समझते हुए भी दिन रात असामाजिक तत्वों की आलोचना में ही व्यस्त रहते हैं। अन्ना हजारे सरीखे समझदार व्यक्ति भी इस तरह शराब या सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सकिय रहते हैं जैसे कि उन्हें सामान्य काल तथा आपात्काल के बीच का अन्तर ही पता न हो।

आपने भी पिता पुत्री अवैध शारीरिक संबंधों की बात उठाकर वैसी ही भूल की है। यह समय आपात्काल है। ऐसे समय में ऐसी बातों को प्राथमिक समझकर अनावश्यक परेशान होना ठीक नहीं। यदि कोई ऐसा करता है तो हम उसे अच्छा नहीं मानेंगे किन्तु हम ऐसे कार्य को इतना महत्वपूर्ण भी न बनने दें कि बलात्कार जैसे अपराध इसके समक्ष छोटे दिखने लग जायें। समाज वैसा बुरा नहीं है जैसा हम लोग बताने लगते हैं। आज भी समाज में अपराधी तत्वों का प्रतिशत चार पांच से कम है किन्तु यदि हम आप सरीखे लोग ही असामाजिक और समाज विरोधी को एक मानने लग जायेंगे तो उनका प्रतिशत तो निन्यान्नवे दिखने ही लग जायेगा।

2. श्री सत्यदेव गुप्त सत्य, रुदौली, बाराबंकी, उत्तरप्रदेश

आपकी रुदौली यात्रा की श्रोताओं पर अच्छी छाप पड़ी। हिन्दुत्व वादी संगठनों को आपसे जैसी उम्मीद थी वैसा न पाकर कछ निराशा हुई दूसरी ओर तथाकथित धर्म निरपेक्ष श्रोताओं को आपके विचारों में अनुमान से ज्यादा तटस्थता दिखी। फिर भी मेरे विचार में प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छे स्तर का रहा। समय रहता तो और अधिक सुनना उपयोगी रहता।

एक कविता प्रस्तुत है
ज्ञान तत्व के पृष्ठों से लें नई चेतना
नव जागृति के नये चित्र बहु विधि उकेरना।
आवाहन करता हूँ सबका बांह पसारे
ओ समाज के प्रहरी आओ साथ हमारे।
नये प्रात पर नई सुरभि पग–पग बिखेरना
रक्त बीज हैं जो समाज के उन्हें घेरना ।।
विविध रंग जीवन के भारी आपाधापी
रचें नया संगीत त्यागकर राग विलापी ।
संकट, चिंता, व्यथा, विफलता और वेदना
छंटे सभी नैराश्य नई लय ताल छेड़ना ।
हो समाज के गौरव तो यह नहीं भूलना
बिना श्रम मिले सम्मानों पर नहीं फूलना ।
मिथ्या दम्म अंध श्रद्धा का गला रेतना
युवा हृदय झकझोर उठे इतना कुरेदना ।।
ज्ञान तत्व के पृष्ठों से लें नई चेतना
नव जागृति के नये चित्र बहु विधि उकेरना।।

3श्री बहादुर सिंह यादव, धनारी, भीम नगर, उत्तरप्रदेश

प्रश्न– केन्द्र सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट देने का प्रस्ताव किया जो विपक्ष के भारी विरोध के कारण स्थगित किया गया है। आप यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि सरकार तथा विपक्ष के बीच स्पष्ट टकराव में किसका पक्ष ठीक है। इस प्रस्ताव से जनता को लाभ है या हानि।

उत्तर– साम्यवादी दल तो सैद्धान्तिक रूप से ऐसे विदेशी निवेश के विरोधी होते हैं। यदि ऐसा निवेश रूस चीन से होता तो साम्यवादियो का व्यवहार अलग होता। भाजपा का कोई सिद्धान्त नहीं है। सरकार मे भाजपा रहे तो अलग ढंग से सोचती है और विपक्ष मे रहे तो अलग। फिर भी व्यापारी समुदाय के हित में भाजपा का विरोध स्वाभाविक है। लालू, मुलायम, मायावती और ममता बनर्जी का विरोध राजनैतिक सौदेबाजी से अलग कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी अपने उदारीकरण के मार्ग पर चलने के हिसाब से चल रही है। किसी ने कोई जनहित का आकलन नहीं किया है, न सरकारी पक्ष ने न ही विपक्ष ने।

व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट सिद्धान्ततः गलत होती है क्योंकि ऐसे प्रतिबन्ध समाज में राज्य के हस्तक्षेप के मार्ग खोलते हैं। इस तरह खुदरा व्यापार में खुले निवेश पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध सिद्धान्ततः गलत हैं। ऐसे किसी भी कदम से उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को हमेशा नुकसान ही होता है क्योंकि बीच के व्यापारियों अथवा अन्य बिचौलियों को जो लाभ होता ह वह लाभ निश्चित रूप से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को आंशिक रूप से नुकसान करेगा ही। यह किसी भी रूप में ऐसा कार्य नहीं जो बीच के लोगों को तो लाभ दे किन्तु मूल घटकों अर्थात उत्पादक उपभोक्ता को कोई नुकसान न करें। इस तरह खुले व्यापार के बीच सरकारी दीवारं टूटनी ही चाहियें चाहे ऐसी दीवारें प्रादेशिक सरकारों की हों या राष्टीय अथवा विश्व स्तरीय। मेरे विचार से ऐसे निवेश को छूट देकर सरकार ने राजनैतिक दृष्टि से भले ही गलत किया हो किन्तु सामाजिक दृष्टि से उसका कार्य लोक को मजबूत और तंत्र को कमजोर करने वाला ही है। इस कदम से सरकार का हस्तक्षेप व्यापारिक क्षेत्र मे कम होना निश्चित है।

इस का एक दूसरा पक्ष भी विचारणीय है कि इस छूट से भारत के छोटे या मझले व्यापारियों को बहुत हानि होगी तथा ऐसी हानि का फायदा बड़े व्यापारी विशेषकर विदेशी व्यापारी उठायेंगे। हजारों छोटे व्यापारियों को बेरोजगार करके बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में व्यापार और उसका लाभ केन्द्रित हो जायें यह भी तो ठीक नहीं। सत्ता का केन्द्रीयकरण घातक है तो धन का केन्द्रीयकरण भी तो घातक है। अतः हमें ऐसा मार्ग निकालना होगा कि सत्ता का हस्तक्षेप भी घटे और व्यापार का केन्द्रीयकरण भी न हो। व्यापार के केन्द्रीयकरण में प्रमुख भूमिका है सस्ती कृत्रिम उर्जा तथा उच्च तकनीक की। जो व्यक्ति जितना ही अधिक सस्ती उर्जा तथा उच्च तकनीक का उपयोग करेगा वह उतना ही अधिक आगे बढ़ता जायेगा। हम उर्जा पर कर न लगाकर उसके द्वारा उत्पादित माल पर कर लगाते हैं। यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बहुत बढ़ा दिया जाये तो बड़े बड़े व्यापारी उतनी आसानी से व्यापार केन्द्रित नहीं कर पायेंगे। खास कर विदेशी कम्पनियॉ तो बिल्कुल ही नहीं कर पायेंगी क्योंकि आवागमन के किराये बढ़ जाने से न कच्चा माल कम भाड़े में आ सकेगा न ही पका माल कम भाड़े में वापस जा सकेगा। आवागमन महगां होने के बाद हम उत्पादन पर लगने वाले टैक्स कम कर देगें। इससे दूर से होने वाला आवागमन अधिक महगां हो जायगा तथा नजदीक का सस्ता । स्वाभाविक है कि बडे उद्योग परेशान होगे और छोटे उद्योग लाभ मे। श्रम आधारिक उद्योग और भी अधिक लाभ मे रहेगें। इसतरह उद्योगो का बडे उद्योगो से छोटे उद्योगो की ओर तथा छोटे उद्योगो का हस्तचलित उद्योगो की ओर विकेन्द्रीकरण होगा। यदि जरूरी हुआ तो उच्च तकनीक में खर्च होने वाली कृत्रिम उर्जा का मूल्य पचीस गुना तक कर दिया जाये। यदि कम्प्यूटर में खर्च होने वाली बिजली पचीस गुना कर दी जाये तो स्वाभाविक है कि उच्च तकनीक सामान्य तकनीक का शोषण नहीं कर पायेगी। किसी भी व्यवस्था प्रमुख को अर्थ नीति इस प्रकार बनानी चाहिये कि श्रम और बुद्धि के बीच संतुलन बना रहे। व्यवस्था प्रमुख का स्वभाव होता है कि वह ऐसे संतुलन को बुद्धि के पक्ष में झुका देता है। वह लगातार कृत्रिम उर्जा तथा नई तकनीक की ओर झुकता चला जाता है। उसका स्वयं का जीवन स्तर उॅचा होता जाता है और उसी के साथ साथ उसकी श्रम और श्रमजीवियों के साथ दूरी बढ़तो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि यह दूरी न बढ़े तो हमें चाहिये कि हम सब प्रकार के प्रशासनिक प्रतिबंध तो समाप्त कर दें तथा कृत्रिम उर्जा का मूल्य इस सीमा तक बढ़ा दें कि श्रम और बुद्धि के बीच की दूरी एक सीमा से आगे न बढ़ पायें। आवागमन का महगां होना किसी भी दृष्टि से गरीब ग्रामीण श्रम जीवी के विरूद्ध नही है। आवागमन का सस्ता होना अथवा उच्च तकनीक का सस्ता होना अवश्य ही गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के विरूद्ध है। पूरी दुनियॉ के पूंजीवादी देशो मे यह नीति इसलिये सफल है कि वे श्रम अभाव देश है।जबकि भारत इसके ठीक विपरीत श्रम बहुल देश। इसलिये हमारी नीतियां भी भारत की परिस्थितियो के अनुसार ही होनी चाहिये।

4श्री एम. एल. श्रीधर, भगवान गंज, सागर, मध्यप्रदेश

प्रश्न– ज्ञान तत्व 236 भावी भारत का संविधान भाग दो प्राप्त हुआ। इसका पहला भाग एक ज्ञान तत्व दो सौ पैंतीस के रूप में तथा दूसरा भाग 236 के रूप मे मिला था। बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। आपने अंक 236 में लिखा कि कानून की नजर में सभी पशु समान होंगे। मैं इससे सहमत नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहॉ गाय विशेष महत्व रखती है। गाय भारत के करोड़ों लोगां की आस्था का केन्द्र है। वैदिक काल में भी गाय का विशेष स्थान था। वैसे भी आप आर्य समाज से जुड़े हैं। फिर आपने गोवध के सम्बन्ध में ऐसा कैसे लिख दिया?

उत्तर– मैं गोवध के पूरी तरह विरुद्ध हूॅ किन्तु मैं गोवध बन्दी के लिये किसी प्रकार के कानून के पक्ष में नहीं। मेरा मानना है कि कृषि प्रधान भारत में गाय की उपयोगिता घट रही है। खेतों की जुताई में बैलों का उपयोग नहीं हो रहा। दूध सस्ता होने से गोपालक भी घाटे का व्यवसाय मानने लगे हैं। यदि शुद्ध घी शुद्ध दूध की मांग बढ़े तो गाय पालना लाभ प्रद होगा। यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़े तो बैल उपयोगी होंगे और जबतक गाय या गो वंश की उपयोगिता नही बढेगी तबतक कानून लाभदायक नही होगा।

मैं समान नागरिक संहिता का पूरी तरह समर्थक हूॅ। आज भारत में हिन्दुत्व खतरे में है। हिन्दुत्व के मूल गुण नष्ट हो रहे हैं। यदि हिन्दुत्व बच गया तो गाय गंगा सब बच जायेंगे किन्तु यदि गाय गंगा सब बचे रहे और हिन्दुत्व घटता चला गया तो न गाय बचेगी न गंगा। आज भारत में गुणात्मक रूप से भी इस्लाम बढ़ रहा है तथा पहचानात्मक रूप से। समान नागरिक संहिता गो हत्या बन्दी में तो बाधक होगी किन्तु इस्लाम की बाढ़ रोकने में ज्यादा सहायक होगी। अधिकांश मुसलमान समान नागरिक संहिता के बिल्कुल विरुद्ध हैं। अतः मेरा अब भी मत है कि समान नागरिक संहिता को ज्यादा महत्व दें और उसके लिये गोहत्या का मुद्दा छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दें। ऐसा संभव नहीं कि अन्य मामलों में तो समान नागरिक संहिता हो और गाय के मामले में हिन्दुओं को विशेष छूट मिले। क्योकि समान नागरिक संहिता तथा हिन्दुओ को विशेषाधिकार बिल्कुल विपरीत अवधारणा है। दुर्भाग्य से दोनो को एक साथ उठाकर समान नागरिक संहिता को कमजोर करने का अप्रत्यक्ष प्रयास हुआ। अब ऐसी भूल नही होनी चाहिये। और इसलिये गाय के मुद्दे को किनारे करना ही उचित होगा।

5.श्री वैधराज आहूजा, भानुप्रतापपुर, कांकेर, छ. ग.

प्रश्न– आप टीम अन्ना की बहुत तारीफ करते हैं। टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य प्रशांत भूषण ने कश्मीर संबंधी एक बयान दिया जिसे श्री राम सेना तथा भगत सिंह सेना के कुछ लोगों ने विरोध प्रकट करते हुए उन्हें पीटा। आप इस पूरी घटना को कैसा मानते हैं। अन्ना जी ने कश्मीर को भारत का निर्विवाद अंग बताया। आप इस मारपीट की घटना तथा बयान के विषय में क्या सोचते हैं?

उत्तर– प्रशान्त भूषण जी ने कश्मीर सम्बन्धी अपने बयान में यह कहा था कि यदि कश्मीर विवाद नहीं निपटता है तो हम उक्त भूभाग के निवासियों को जनमत संग्रह कराकर उन्हें स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दे दें। पहला विचारणीय प्रश्न यही है कि यह सुझाव कितना उचित है।

मैं भी बीस पचीस वर्ष पूर्व ऐसा ही सोचता था। मैंने कई जगह लिखा भी कि पाकिस्तान की मांग न्यायोचित है क्योंकि भारत विभाजन के समय कश्मीर और हैदराबाद स्वतंत्र राष्ट थे। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के पूर्व देशी रियासतों को यह छूट दी थी कि ये भारत या पाकिस्तान म से किसी एक के साथ मिल भी सकती हैं या चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। अन्य रियासतें तो कहीं न कहीं मिल गईं किन्तु हैदराबाद और कश्मीर टालमटोल करते रहे। हैदराबाद की जनता हिन्दू थी और राजा मुसलमान। कश्मीर की जनता मुसलमान थी और राजा हिन्दू। भारत ने आक्रमण करके हैदराबाद को मिला लिया और पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की किन्तु कश्मीर के राजा हरिसिंह ने हारने के बदले भारत के साथ कुछ शर्तों पर विलय कर दिया। भारत की सेनाऍं बढ़ने लगीं किन्तु मामला राष्ट संघ में चला गया और भारत ने राष्टसघ की सलाह पर जनमत संग्रह स्वीकार कर लिया।

पाकिस्तान ने कश्मीर में धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया और भारत ने कश्मीर वासियों को आर्थिक सुविधाऍं देकर दिल जीतना चाहा। धीरे धीरे कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच के राजनैतिक विवाद से निकलकर हिन्दू और मुसलमान के बीच का धार्मिक विवाद बनने लगा। विश्व इस्लामिक बिरादरी ने कश्मीर के मुसलमानों के धार्मिक विचारों को कुरेदना शुरू किया तो भारत के कुछ कहरवादी हिन्दुओं ने गांधी हत्या के द्वारा अथवा कश्मीर भारत के बीच विलय की शर्तों को तोड़ने की मांग उठा उठा कर कट्टरवादि मुसलमानों का मार्ग आसान कर दिया। विश्व इस्लामिक बिरादरी को सुविधा हुई और वे कश्मीरी मुसलमानों को यह समझाने में सफल रहे कि भारत मूलतः एक हिन्दू राष्ट है। कुछ कहरवादी हिन्दुओं की नासमझी ने हमारी धर्म निरपेक्षता को संदेहास्पद बना दिया। लगा कि हम विश्व जनमत के समक्ष भी अलग थलग पड़ रहे हैं तथा पूरे भारत का पेट काटकाट कर बेतहाशा धन कश्मीर के ऐसे लोगों की राहत पर खर्च कर रहे हैं जो कभी अपने हो ही नहीं सकते। सैनिक खर्च तो इससे अलग था ही। ऐसी स्थिति में मैंने सुझाव दिया कि हमें कश्मीर समस्या को किसी न किसी रूप से निपटा लेना चाहिये भले ही कुछ देना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं।

कुछ वर्षों के बाद मेरे विचार बदले। मुझे लगने लगा कि कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान जैसे दो देशों के बीच की समस्या न होकर हिन्दू और मुसलमान जैसे दो धर्मों के बीच की समस्या है। इस्लाम का मूल चरित्र संगठन प्रधान है और हिन्दुत्व का आचरण प्रधान। इस्लाम की सर्वोच्च प्राथमिकता है दारूल इस्लाम। वह स्वयं को शेर और हिन्दुत्व को गाय के समान मानता है। वह मानता है कि गाय को खाना उसका प्रकृति विरूद्ध आचरण नहीं है। सूफी सन्तों ने शेर को शाकाहारी बनाने की भरसक कोशिश की किन्तु सफल नहीं रहे। उसी तरह संघ परिवार ने भी गाय को शेर बनाने की कोशिशें की किन्तु सफल नहीं रहे। इस्लाम और हिन्दुत्व के बीच का यह फर्क ही कश्मीर समस्या है। पाकिस्तान पर इस्लाम का प्रभुत्व है। विश्व इस्लामिक बिरादरी का भी उग्रवादी तबका कश्मीर में सक्रिय है तो पाकिस्तान की तो मजबूरी है कि वह वहॉ सक्रिय रहे। उसे तो कश्मीर विजय से दुहरा फायदा होगा। इस तरह यह लड़ाई कश्मीर के न्याय अन्याय के आधार पर विचारणीय मुद्दा न होकर शोषक और शोषित के बोच का मसला बन गया है। कल्पना करिये कि यदि स्वतंत्रता के समय ही पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेता और भारत न्याय अन्याय की मांग करता तब क्या पाकिस्तान इस संबंध में कुछ बात करता। तब क्या इस्लाम और हिन्दुत्व के बीच कोई चर्चा होती? आज जिस तरह भारत में मेरे सरीखे अथवा प्रशान्त भूषण सरीखे लोग यदा कदा कुछ बोल भी देते हैं उस तरह यदि कोई पाकिस्तानी कुछ बोल देता तब उसका क्या हाल होता? कोई आक्रमण से पीडित पक्ष न्याय की आवाज उठावें और कोई आक्रमण कारी पराजित होकर न्याय की मांग करे इन दोनों में अन्तर तो होगा ही।

प्रश्न यह है कि कश्मीर का समाधान न्याय अन्याय के आधार पर होना चाहिये या नीयत के आधार पर। स्पष्ट है कि इस्लाम का पेट कश्मीर से भरने वाला नहीं है। उसे यह विश्वास है कि जो मिले वह लेते जाओ और आगे के लिये झगड़ा पैदा करते जाओ। यदि कश्मीर छोड़ भी दें तो क्या ऐसा कोई विश्वास का आधार है क्या कि पंजाब में ऐसा विवाद नहीं खड़ा कर दिया जायेगा। इस्लाम

हजारों वर्ष तक लड़ने की तैयारी वाला संगठन है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अन्तिम रूप से समझौता नहीं करता। अल्पकाल के लिये किसी रणनीति के अन्तर्गत पीछे हटना एक अलग बात है। इस्लाम को पता है कि किसी अन्य धर्मावलम्बी समूह में इतना धैर्य नहीं कि वह सैकड़ों वर्ष तक प्रतीक्षा करे। हिन्दुओं में तो यह धैर्य बिल्कुल कम है। इसलिये इस्लाम किसी न किसी रूप में टकराव को जीवित रखना चाहता है कि हिन्दू लोग कभी न कभी तो कश्मीर में थकेंगे ही। और अब तक भारत थक भी गया होता यदि इस्लाम को अमेरिका आदि देशों से चुनौती न मिली होती। इस्लाम जिस तरह पूरी दुनिया में अनेक स्थानों पर विवाद पैदा करके अब तक जीतता रहा है उससे उसका मनोबल बढ़ा। इस्लाम इस मनोबल बढने के परिणाम स्वरूप नये नये विवाद पैदा करता रहा। इस्लाम की इसी प्रवृति ने मेरे जैसे व्यक्ति को भी सावधान किया कि साम्प्रदायिक भावनाओं को कभी समझाया नहीं जा सकता। उन्हें तो दबाया ही जा सकता है। और यदि साम्प्रदायिकता उग्रवाद के कन्धे पर सवार हो जाये तो उसे तो कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। उसे तो कुचला ही जा सकता है। यदि साम्प्रदायिकता आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दे तो उसे तो तत्काल नष्ट करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं। दुर्भाग्य है कि हम घोषित आतंकवादियों तक के हृदय परिवर्तन से लेकर न्याय सगत चर्चाओं की चर्चा करते रहते हैं। हम उन पृथ्वीराजों को कैसे और क्या समझायें जो आज भी मुहम्मद गोरी को बार बार माफ करने वाले पृथ्वीराज की प्रशंसा को ही शान की बात समझते हैं।

प्रशान्त भूषण जी के साथ एक और विषय जुड़ा है कि उनके इस बयान का गलत मानकर कुछ लोगों ने उन पर हिंसक आकमण किया। हिंसा का मार्ग तभी अपनाया जा सकता है जब ;1द्ध किसी व्यक्ति के किसी मूल अधिकार पर आकमण होता हो ;2द्ध अपनी सुरक्षा का कोई अन्य माध्यम अपलब्ध न हो ;3द्ध जीतने की पूरी पूरी संभावना हो ;4द्ध दोनों पक्षों में से कोई षि एक भावना प्रधान न हो। प्रशान्त भूषण के कथन से क्षुब्ध आकमण कारियों के किसी मौलिक अधिकार अथवा अधिकारों के विरूद्ध हमला नहीं हुआ था न ही न्याय प्राप्ति के अन्य सभी मार्ग बन्द हुए थे। सिर्फ एक ही आधार उपलब्ध था कि मारपीट करने वालों का जोतना निश्चित था। उन्होंने प्रशान्त भूषण जी पर जो शारीरिक आकमण किया वह साफ तौर पर गुण्डागर्दी थी और ऐसे आकमण का समर्थन भी किसी प्रकार उचित नहीं था। प्रशान्त भूषण का कथन गलत था तो उक्त कथन के विरूद्ध तर्क देना हमारी भारतीय परंपरा रही है और ऐसे गलत कथन के विरूद्ध तर्क का सहारा न लेकर हमला करना या मारपीट करना इस्लामिक परंपरा रही है। जिनके तर्कों में दम नहीं होता ये ही ऐसे आकमण का सहारा लेते हैं और हम पूर्व में भी ऐसे इस्लामिक परंपराओं के परिपालन में पण्डित लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा गाधी जैसे अनेक महा पुरूषों का बलिदान दे चुके हैं। अब तो कम से कम ऐसी परंपराओं पर रोक लगनी चाहिये।

मैं अब भी इस मत का हूँ कि प्रशान्त भूषण जी का कथन गलत तर्कों पर आधारित था तथा परिस्थितियों के विपरीत था। इस्लाम की विस्तारवादी नीति को ठीक से समझते हुए ही न्याय की बात संभव है अन्यथा न्याय मूर्खता माना जायेगा। साथ ही प्रशान्त भूषण जी पर हिंसक आकमण साफ तौर पर इस्लामिक प्रणाली का अनुकरण है और यह भी उनके कथन की अपेक्षा ज्यादा ही घातक है। हमें चाहिये कि हम ऐसे मामलों में सोच समझकर ही निर्णय करें।

6.श्री आकाश अशेष, टुन्डला, फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश

प्रश्न–बहुत वर्ष बाद आपकी याद आई। लगता है कि आजकल भारत में भ्रष्टाचार विरोध की जो आंधी उठ खड़ी हुई है उसे आप जैसे मौलिक चिन्तक के मार्ग दर्शन की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि टीम अन्ना के पास कान्ति को नई दिशा देने का युगबोध कुछ भटक रहा दिखता है। मेरी इच्छा है कि आप इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन के भारतीय करण करने में अपना योग दान देने की कृपा करें। आप आन्दोलन की समीक्षा भी करें।

उत्तर– मेरे विचार में टीम अन्ना के भारतीय करण का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तक पूरा आंदोलन भारतीय परिवेश में ही होता रहा है। अबतक टीम अन्ना का एक भी कदम भारतीय परिवेश के विपरीत नही गया है। यहॉ तक कि टीम अन्ना को उकसाने के लिये दिग्विजय सिंह सहित अनेक लोगो ने बहुत नीचे उतरकर प्रयास किये । लालू प्रसाद मुलायम सिंह शरद यादव ने क्या क्या नही कहा । शायद और कोई होता तो विचलित भी हो जाता । किन्तु अन्ना जी ने बहुत अधिक शालीनता और धैर्य से काम लिया।

आपने आंदोलन को भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंधी समझा जो आपकी भूल है। टीम अन्ना से भी यही भूल हुई है। सच बात यह है कि यह आंधी वर्तमान राजनैतिक वातावरण के विरूद्ध उठी थी जिसे टीम अन्ना सरीखा विश्वसनीय नेतृत्व तथा भ्रष्टाचार विरोध का बहाना मिला। भ्रष्टाचार विरोध ऐसी आंधी का मूल श्रोत नहीं था।

आपने मार्गदर्शन की बात कही। टीम अन्ना के सदस्यो के साथ मेरा निरंतर सम्पर्क रहा है। उन्होंने जो आंदोलन किया उसमें मेरा लगातार समर्थन और सहयोग रहा है और अब भी है। जहॉ तक मार्गदर्शन की बात है तो यदि टीम को ऐसी आवश्यकता होगी तो मैं उनके साथ हूँ ही। वैसे अब तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। वे जो भी कर रहे हैं उससे मेरी प्रारंभ से ही आंशिक सहमति आंशिक असहमति रही। फिर भी कुल मिलाकर उनका प्रयत्न इमानदार था, समाज के लिये उपयोगी था किन्तु परिणाम आंशिक ही होने की संभावना थी। इसलिये मुझे समर्थन सहयोग तक ही सीमित रहना उचित लगा।

टीम अन्ना भी महसूस कर रही है कि उनका लोकपाल आंदोलन चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। कहॉ भूल हुई और कहॉ धोखा हुआ उसकी समीक्षा करते हुए आगे की राह खोजने का नाम है चौराहे पर खड़ा होना। निश्चित रूप से कुछ भूलें हुई हैं

1- भ्रष्टाचार हमारी राजनतिक अव्यवस्था का कारण नहीं है, परिणाम है। परिणामों के प्रभावों को कम करना या दूर करना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। यह तो व्यवस्था में सुधार मात्र तक सीमित है। अव्यवस्था के कारणों को दूर करना व्यवस्था परिवर्तन होता है। सत्ता का केन्द्रीय करण भ्रष्टाचार का कारण है तथा अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण उसका समाधान। भ्रष्टाचार दूर करने के प्रयत्न वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में सुधार के प्रयत्न मात्र हैं। जब व्यवस्थापक की नीयत ठीक हो नीति गलत तब व्यवस्था में सुधार की कोशिश होनी चाहिये। टीम अन्ना यह नहीं समझ सकी कि व्यवस्थापकों की नीयत खराब है अन्यथा वह भ्रष्टाचार के विरूद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू न करके लोक संसद का संघर्ष शुरू करती।

2- अठाइस अगस्त दो हजार ग्यारह को वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था का मनोबल सर्वाधिक गिरा हुआ था तथा टीम अन्ना का उपर। उसी समय लोकपाल आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिये था। उससे नये विषय पर नया आंदोलन करने की हिम्मत बनी रहती। न भ्रष्टाचार नियंत्रण हमारा लक्ष्य था न लोकपाल। भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन के माध्यम से हम तंत्र के समक्ष शक्ति प्रदर्शन में पूरी तरह सफल हो चुके थे। बाइस अगस्त दो हजार ग्यारह को ही हम लोगों ने चिट्ठी लिखकर टीम अन्ना से निवेदन किया था कि लोकपाल के टकराव स कहीं सम्मान जनक तरीके से पिण्ड छुड़ाकर लोक संसद का प्रश्न खड़ा करना चाहिये। मेरे विचार ने ऐसा न करके लोकपाल मुद्दे से ही चिपके रहना दुसरी भूल हुई । 28 अगस्त

को ही विजय जुलूस निकलने के बाद लोकपाल आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिये श्था तथा नये विषय पर नये आंदोलन की तैयारी मे लग जाना चाहिये था।

3- जब कांग्रेस पार्टी ने और आगे झुकने से इन्कार कर दिया तब टीम अन्ना को हरियाणा के एक सीट के चुनाव में प्रत्यक्ष न कूदकर सिर्फ दबाव तक ही सीमित रहना चाहिये था। किसी के उपर दबाव बनाने को कार्यान्वित करना हो तो उसे और ज्यादा सोचना चाहिये था। हिसार के उप चुनाव मे तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनावो मे भी टीम अन्ना की भूमिका उचित नही कही जा सकती है।क्योकि अब दबाव की सीमा दबाव तक न रहकर टकराव की दिशा मे जाने लगी। तब सोच समझकर ही टकराव का निर्णय होना चाहिये। दबाव बनाते समय तो सामान्य रूप से भी निर्णय हो सकता है। टीम अन्ना ने दबाव के समय अपनाई गयी रणनीति को ही टकराव के समय भी उसी तरह शुरू कर दिया। यह भूल थी।

4- जब सरकार न लोक सभा के सत्र की अवधि पाच दिन बढाकर उन्तीस तक कर दी तब सत्ताइस से ही अनशन प्रारंभ करनाविल्कुल ही गलत कदम था। प्रारंभ से ही जो तीन भूले हुई उनका परिणाम अप्रत्यक्ष था। किन्तु सत्ताइस तारीख से होने वाले अनशन ने सारी हवा ही निकाल दी। फिरभी टीम अन्ना इस बात क लिये बधाई के पात्र है कि उसने समय की नब्ज पहचान कर अनशन दूसरे दिन ही खतम कर दिया। यदि अनशन एक दिन और चलता तो ज्यादा भूल हो जाती।

पूरें घटना कम से स्पष्ट है कि अन्ना जी ने जो आंदोलन किया उसने समाज मे एक आत्मविश्वास पैदा किया है कि लोक और तंत्र के बीच यदि कोई सीधा टकराव होता है तो लोक तंत्र पर भारी पडेगा। स्पष्ट दिखता है कि लोक और तंत्र के बीच सीधा टकराव होगा तो लोक तंत्र पर भारी पडेगा । होना यह चाहिये कि लोक और तंत्र के बीच सीधा ध्रुवीकरण हो । बीच का मार्ग हमारे पास नहो है और ऐसे ध्रुवीकरण के लिये लोकसंसद आंदोलन ही सबसे अच्छा मार्ग है। टीम अन्ना अब राजनीति मे सुधार या अन्य कोई छोटा मोटा आंदोलन करने के बजाय लोक संसद का निर्णायक आंदोलन शुरू करे । यदि टीम चूक जायगी तो स्वाभाविक है कि कोई अन्य इस मांग को उठा सकता है। और वैसी परिस्थिति मे हम तो उस टीम का भी पूरा समर्थन सहयोग करने को तैयार है जैसा हमने अबतक टीम अन्ना के आंदोलन का किया है।

अपनो से अपनी बात

नवंबर और दिसम्बर में दो माह की उत्तर भारत की व्यवस्था परिवर्तन यात्रा तथा इस बीच अन्ना आंदोलन के परिणामों को देखने के बाद अन्तिम रूप से निष्कर्ष निकला है कि ;1द्ध वर्तमान भारतीय राजनैतिक वातावरण में सत्ता का राजनेताओं के पास इकट्ठा होना ही सबसे बड़ी समस्या है ;2द्ध सभी राजनैतिक दलों का इस संबंध में सोच एक समान ही है कि किसी भी परिस्थिति में राजनेताओं के अधिकारों में कभी न हो। ;3द्ध राजनीति से जुड़े सभी व्यक्ति अधिकारों की छीना झपटी में निरंतर लगे हुए हैं भले ही उनमें कोई इमानदार ही क्यों न हो।

ऐसी परिस्थिति में लोक संसद का आंदोलन ही एकमात्र मार्ग है। लोक संसद ऐसे दलों पर भी अंकुश लगायेगी तथा राजनेताओं पर भी। अतः अन्य सभी आन्दोलनों को छोड़कर सिर्फ लोक संसद के ही आंदोलन को आगे बढ़ाना उचित होगा।

लोक संसद हमारे संघर्ष का एकमात्र आधार होना चाहिये। व्यवस्था परिवर्तन अभियान प्रारंभ से ही मानता रहा है कि भ्रष्टाचार राजनैतिक शक्ति के एकत्रीकरण का परिणाम है, कारण नहीं। अर्थात् जब तक राजनैतिक शक्ति विकेन्द्रित नहीं होगी तब तक न भ्रष्टाचार घटेगा न अन्य समस्याएँ घटेंगी। हमारी बात न रामदेव जी ने कभी मानी और न अन्ना जी ने। दोनो ने ही राजनेताओं के आपसी टकराव से लाभ उठाने की कोशिश की । दोनो भूल गये कि राजनेताओ का आपसी टकराव अधिक से अधिक शक्ति अपने पास एकत्रित करने तक ही सीमित है। यदि उन्हें लगा कि यह टकराव लोक के पक्ष में जाकर उनके अधिकारों में कटौती करेगा तो ये सब एक हो जायेंगे। आखिर हुआ वही। अतः अब कोई नया प्रयोग न करके लोक संसद के नाम पर आर पार का संघर्ष होना चाहिये। यदि रामदेव जी या अन्ना जी इस दिशा में पहल न करें तो कोई और जो भी करे। हम सबको उसके पक्ष में एकजुट हो जाना चाहिये। अब निर्णायक संघर्ष की आवाज बुलंद करने का समय आ गया है और वह एकमात्र आवाज है लोक संसद।

लोक संसद के लिये संघर्ष तो सामाजिक संकट की एक दवा मात्र है किन्तु हमारे लिये इसके साथ साथ दो काम करने और आवश्यक हैं। ;1द्ध समाज सशक्ति करण अभियान ;2द्ध मानसिक व्यायाम। समाज सशक्तिकरण के लिये ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान पर्याप्त है। ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान का प्रारंभिक प्रयोग रामानुजगंज के आस पास के एक सौ तीस गांवों में प्रारंभ है। सितम्बर तक इसकी सफलता का आकलन किया जायेगा। आप उसकी विधि और उसके परिणाम समझ सकत हैं। मानसिक व्यायाम व्यक्तिगत ज्ञान विस्तार का आधार है। यदि आप मानसिक व्यायाम द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाने में सकिय होंगे तो आपको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लाभ तो होगा ही साथ ही सामाजिक लाभ भी बहुत होगा। इस तरह ये तीन कार्य मिलकर व्यवस्था परिवर्तन का निश्चित परिणाम दे सकते हैं। यह इस सम्पूर्ण दो माह की यात्रा का निष्कर्ष है।

आपसे निवेदन है कि आप गांव गांव में केन्द्र बनाकर मानसिक व्यायाम की शुरूआत कर सकते हैं। पचीस तीस ज्ञान तत्व के पाठकों के नाम भेजकर इसकी शुरूआत कर सकते हैं। ज्ञान तत्व पढ़ते पढ़ते आपका व्यायाम होने लग जायेगा। सितम्बर बीस से छब्बीस के बीच की तारीख तय करके रामानुजगंज में सात दिन का मानसिक व्यायाम शिविर भी करने की योजना है। इस सात दिवसीय शिविर में आप मानसिक व्यायाम शिविर का लाभ उठा सकेंगे। इन सात दिनों में आप रामानुजगंज के गांवों मे घूम कर नई समाज रचना का प्रयोग भी देख सकेंगे। इस तरह इस शिविर से दुहरा लाभ होगा।

इस शिविर के अन्तिम दो दिन पच्चीस और छब्बीस सितम्बर को लोक संसद आंदोलन की रूप रेखा पर भी चर्चा होगी। लोक संसद के लिये देश भर में वातावरण बनना ही चाहिये। ऐसे वातावरण की चर्चा इस शिविर सह सम्मेलन का तीसरा लाभ होगा। इस सात दिवसीय शिविर सम्मेलन का नाम व्यवस्था परिवर्तन सम्मेलन रखा जा रहा है। आप अधिक से अधिक साथियों के साथ सम्मेलन में शामिल हों। भोजन निवास तथा ग्राम दर्शन की व्यवस्था हम करेंगे।

अन्ना जी के आंदोलन के परिणाम देखने के बाद अब आवश्यक हो गया है कि आप लोक संसद की दिशा में सकिय हों। व्यवस्था परिवर्तन अभियान के सभी साथी आपका पूरा समर्थन सहयोग करेंगे तथा यदि सितम्बर सम्मेलन में कोई योजना बनी तो सहभागिता के लिये भी तैयार रहेंगे।